नव भारत
| संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्त्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी |

आर्थिक सर्वेक्षण : सुधार और संभावनाओं की तस्वीर

गुरुवार को संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक यात्रा का आत्मविश्वास से भरा बयान भी है. 1 फरवरी को आने वाले केंद्रीय बजट से ठीक पहले पेश किया गया यह सर्वेक्षण सरकार की प्राथमिकताओं, चुनौतियों और दीर्घकालिक दृष्टि को स्पष्ट करता है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने जिस तरह स्थिरता और गति का संतुलन बनाए रखा है, वह इस सर्वेक्षण का केंद्रीय संदेश है.

सर्वेक्षण के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.3 से 7.5 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है. यह संकेत देता है कि वैश्विक मंदी, युद्ध और व्यापारिक तनावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है. वहीं 2026-27 के लिए 6.8 से 7.2 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर यह भरोसा दिलाती है कि भारत की विकास गाथा केवल अस्थायी उछाल नहीं, बल्कि संरचनात्मक मजबूती पर आधारित है.

महंगाई के मोर्चे पर भी सर्वेक्षण राहत देता है. खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे में बनी हुई है. जीएसटी ढांचे में सुधार, आपूर्ति श्रृंखला के बेहतर प्रबंधन और सरकारी हस्तक्षेपों ने कीमतों को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाई है. यह संतुलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास की रफ्तार तभी टिकाऊ होती है जब आम नागरिक पर महंगाई का बोझ सीमित रहे.

हालांकि सर्वेक्षण चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं करता. वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, संरक्षणवादी नीतियां और कुछ देशों द्वारा टैरिफ बढ़ाने की प्रवृत्ति भारतीय निर्यात के लिए जोखिम पैदा कर सकती है. इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये का करीब 92 के स्तर तक पहुंचना बाहरी झटकों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी देता है. सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति ही ऐसे समय में सुरक्षा कवच बन सकते हैं. सेक्टर-वार प्रदर्शन की बात करें तो कृषि क्षेत्र ने सामान्य मानसून और ग्रामीण मांग में सुधार के चलते मजबूती दिखाई है. यह संकेत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का है. वहीं विनिर्माण और सेवा क्षेत्र विकास के मुख्य इंजन बने हुए हैं. निजी निवेश में तेजी के संकेत बताते हैं कि कारोबारी विश्वास लौट रहा है और भविष्य की संभावनाओं को लेकर उद्योग जगत आश्वस्त है. प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेखित रिफॉर्म एक्सप्रेस की अवधारणा आर्थिक सर्वेक्षण में ठोस रूप में दिखाई देती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत खर्च को भविष्य की विकास रणनीति का आधार माना गया है. यह दृष्टि स्पष्ट करती है कि सरकार अल्पकालिक लोकलुभावन उपायों के बजाय दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर जोर दे रही है.

कुल मिलाकर, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत की अर्थव्यवस्था की एक संतुलित तस्वीर पेश करता है,जहां चुनौतियां हैं, लेकिन उनसे निपटने का आत्मविश्वास भी है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 1 फरवरी का बजट इस सर्वेक्षण की भावना को कितनी मजबूती से जमीन पर उतार पाता है. यदि सुधारों की यह गति बनी रही, तो भारत न केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की ओर भी ठोस कदम बढ़ाएगा.

सुशासन के जरिए विकास को गति

पंकज जोशी

कुशल शासन की दिशा में भारत की यात्रा अक्सर एक विशाल संघीय ढांचे के तहत कार्यान्वयन से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों को रेखांकित करती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में स्थापित 'प्रगति' [सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इप्लीमेंटेशन)] नामक पहल, नौकरशाही की पेचीदगियों को दूर करने के एक शक्तिशाली तंत्र के रूप में कार्य करती है. एक ओर जहां यह विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं को गति प्रदान करती है, वहीं इसका प्रभाव शायद राज्य स्तर पर सबसे अधिक स्पष्ट होता है. आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण विशिष्ट क्षेत्रीय परियोजनाओं की सटीक निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है. गुजरात में, 'प्रगति' के तहत की गई समीक्षाओं ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा सामाजिक कल्याण से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं में आने वाली अड़चनों को व्यवस्थित रूप से दूर किया है और सहकारी संघवाद के एक मजबूत मॉडल को मूर्त रूप दिया है. 'प्रगति' ने न सिर्फ समीक्षा के एक मंच, बल्कि एक पूर्वानुमानित शासन के रूप में भी कार्य किया है. महीने की शुरुआत में अग्रिम रूप से एजेंडा का वितरण राज्य के संबंधित विभागों, जिला प्रशासन और कार्यान्वयन एजेंसियों की केन्द्रित भागीदारी को बढ़ावा देने में सहायक रहा. सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, 'प्रगति' की निर्धारित बैठकों से पहले ही कई समस्याओं का निराकरण हो गया. लिहाजा, ऐसे एजेंडा मदों को अंतिम समीक्षा से हटा दिया गया. यह उच्चस्तरीय हस्तक्षेप से पहले ही राज्य स्तर पर उनके समाधान को दर्शाता है.

राज्य-आधारित तेजी हेतु एक डिजिटल समन्वय- 'प्रगति' की सफलता का मूल राज्य और केन्द्रीय प्रशासन के शीर्ष स्तरों को जवाबदेही-आधारित एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की इसकी क्षमता में निहित है. हर महीने, यह इंटरफेस उन परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा को संभव बनाता है जो अंतर-विभागीय मतभेदों या भूमि अधिग्रहण संबंधी अड़चनों की वजह से रुक सकती हैं.

डीएमआईसी को सीधे प्रधानमंत्री की समीक्षा के अधीन रखकर, 'प्रगति' ने धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और निजी हितधारकों से जुड़ी समस्याओं पर वास्तविक समय में चर्चा किया जाना सुनिश्चित किया. इस प्रक्रिया ने निर्णय लेने की कवायद को गति दी, नौकरशाही में व्याप्त लालफीताशाही को कम किया और सभी संबंधित पक्षों को स्पष्ट व समयबद्ध दिशा-निर्देश प्रदान किए, जिससे भारत के औद्योगिक भविष्य की बुनियाद मानी जाने वाली इस परियोजना को गति मिली. 'प्रगति' के तहत होने वाली समीक्षाओं ने धोलेरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे के बुनियादी ढांचे के समयबद्ध विकास को सुनिश्चित किया है. यह 109 किलोमीटर लंबी एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसे अहमदाबाद को धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) से जोड़ने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है. सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र हेतु कुल 91,000 करोड़ रुपये के मुख्य परियोजना निवेश के साथ, यह इलाका भारत का सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए तैयार है और यहां देश के पहले स्वदेशी चिप्स का उत्पादन होगा. इस राज्य की सीमाओं के भीतर संचालित होने वाली ऐसी उच्च-मूल्य वाली केन्द्रीय परियोजनाएं उस 'प्रगति' तंत्र का हिस्सा बनने की आदर्श हकदार हैं, जो राज्य के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बीच तालमेल सुनिश्चित करती हैं.

गुजरात की हरित ऊर्जा क्रांति को गति- गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है और 'प्रगति' इसकी विशाल क्षमता को मूर्त रूप देने में अहम भूमिका निभा रही है. बड़े पैमाने की विविध सौर एवं पवन परियोजनाएं इस लक्ष्य को रेखांकित करती हैं. कुल 1200 मेगावाट क्षमता वाली खावड़ा सौर पीवी परियोजना (6284 करोड़ रुपये) और 1255 मेगावाट क्षमता वाली खावड़ा सौर पीवी परियोजना (7180 करोड़ रुपये) इस पहल की प्रमुख घटक हैं.

(लेखक आईएएस (सेवानिवृत्त), जीईआरसी के अध्यक्ष/गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव हैं)

बुनियादी ढांचे से परे- सामाजिक दायित्व

'प्रगति' का दायरा भौतिक बुनियादी ढांचे से कहीं आगे जाता है. यह पहल समाज कल्याण की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने और अंतिम छोर तक उनकी सुलभता सुनिश्चित करने में भी समान रूप से प्रभावी है. प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभीम)स्वास्थ्य संबंधी इस महत्वपूर्ण पहल की समयबद्ध और प्रभावी कवरेज सुनिश्चित करने हेतु निगरानी की गई. नागरिकों को मिलने वाले प्रमुख लाभ हैं- उन्नत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के जरिए स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच; देखभाल की बेहतर गुणवत्ता; वित्तीय बोझ में कमी; आईटी-आधारित रोग निगरानी प्रणाली तथा प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के विकास द्वारा महामारी से निपटने की बेहतर तैयारी एवं प्रतिक्रिया; व्यापक प्राथमिक देखभाल; और डिजिटल स्वास्थ्य एकीकरण. पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएमश्री)- स्कूली अवसंरचना के आधुनिकीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस योजना की प्रगति की समीक्षा 'प्रगति' के जरिए की जाती है.

महाकौशल की डायरी

पुष्पा के सिंडीकेट की तरह काम कर रहा अनाज माफिया गिरोह

अविनाश दीक्षित

हिंदी सिनेमा की सुपरहिट हो चुकी पुष्पा के सिंडीकेट की तरह जबलपुर के अनाज माफिया भी गरीबों के राशन को डकारते नजर आ रहे हैं. दुकान विक्रेता, डीलर और ट्रांसपोर्टर का सिंडीकेट गरीबों को मिलने वाले अनाज में डाका डाल रहा है जिसके उजागर होने के बाद चर्चाएं आम हो गईं हैं कि सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने का एक बार फिर से ट्रेंड बदल दिया गया है. पहले निजी अनाज गोदाम से कालाबाजारी का खेल चलता था तो प्रशासन ने वेयरहाउस की निगरानी मुस्तैद कर दी थी लेकिन अब अनाज की कालाबाजारी के लिए ट्रांसपोर्टर एवं

डीलर्स सांठगांठ कर सरकारी अनाज को व्यापारी के फड़ तक चोरी छिपे पहुंचा रहे हैं. ऐसे में प्रशासनिक स्तर की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. जानकारों का कहना है कि इस बड़े घोटाले में जिम्मेदारों की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है.

विदित हो कि राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) के गोदाम से डीलर की दुकान तक वाहनों से अनाज भेजा जाता है जिसके बीच में ही सारा खेल हो रहा है. खबर सरेआम है कि जीपीएस सिस्टम के साथ गेहूं-चावल को वेयर हाउस से लेकर राशन दुकान तक पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टरों ने पूरा सिंडीकेट बनाकर रखा हुआ है. 5 से 25 टन अनाज लेकर संपूर्ण दस्तावेज के साथ वाहन को गंतव्य के लिए रवाना किया जाता है, लेकिन दुकान पहुंचने पहुंचने तक इसकी मात्रा कम हो जाती है. खबर है कि देहात क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टर आधा घंटा में ट्रक में लोड 80 से 100 बोरी बदल देते हैं. टंच अनाज व्यापारी की गोदाम में पहुंच जाता है, और व्यापारी का घटिया अनाज राशन दुकान में पहुंचा दिया जाता है. फिर दुकान संचालक टंच चावल और घटिया को मिलाकर उपभोक्ता को तौल देता है.

नाम बड़े दर्शन छोटे की कहावत फिट बैठी...

नाम बड़े दर्शन छोटे... ये कहावत बीते कुछ दिनों से जबलपुर के बिल्डिंग परमिशन शाखा पर बिल्कुल सटीक बैठती नजर आ रही है. जिसकी मुख्य वजह शाखा के अपग्रेड पोर्टल ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम पर कुछ ही कॉलोनियों का डेटा दर्ज करना, ऐसे में अब भवन निर्माण परमिशन लेने में लोगों को महीनों लग रहे हैं. आलम ये है कि बिल्डिंग अनुमति के लिए शहरवासियों को दफ्तरों के काफी चक्कर काटने पड़ रहे हैं. विदित हो कि बिल्डिंग परमिशन शाखा के पोर्टल पर दर्ज कॉलोनियों के आधार पर ही भवन निर्माण की परमिशन जारी की जाती है, लेकिन शहर में एक सैकड़ा से अधिक कॉलोनियां हैं. जबकि पोर्टल पर आधी ही दर्ज हैं. जानकारी के अनुसार मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन लेने में लोगों को सहूलियत देने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से बिल्डिंग परमिशन के पोर्टल ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम (एबीपास) को अपग्रेड किया था. विगत 1 जुलाई 2025 से पहले एबीपास-2 पर काम चल रहा था. वर्तमान में अपग्रेड वर्जन एबीपास-3 का उपयोग हो रहा है, लेकिन इस अपग्रेडेशन के बाद लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं.

सुर्खियों में सीईओ का बयान

जबलपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ का बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. बयान स्मार्ट सिटी कार्यालय में पदस्थ करीब 26 अधिकारी-कर्मचारियों से जुड़ा है. खबर है कि स्मार्ट सिटी में पिछले 2 साल से कोई काम नहीं है उसके बाद भी वहां के अधिकारी- कर्मचारियों को मुफ्त का वेतन मिल रहा है और इसी वेतन के नाम पर बीते 2 साल में करीब 3 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खाली किए गए हैं. मामले में सीईओ ने जो कहा उससे तो साफ था कि ये सरकारी खजाना अभी और खाली होता रहेगा क्योंकि शासन से अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि स्मार्ट सिटी जबलपुर को खत्म किया जा सके और यहां के अधिकारी-कर्मचारियों को हटाया जा सके. जबकि फिलहाल अभी जबलपुर स्मार्ट सिटी के पास कोई प्रोजेक्ट काम करने के लिए भी नहीं है. सर्वविदित है कि स्मार्ट सिटी का कार्यकाल जून 2023 को ही समाप्त हो चुका है. विदित हो कि शहर को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत 2016 में निर्माण व विकास कार्य शुरू हुए थे लेकिन यहां पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा में प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए. कई विकास कार्यों को एक्सटेंशन दिया गया फिर भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जो अधूरे हैं. जैसे स्मार्ट रोड निर्माण, भूमिगत नाली निर्माण, भूमिगत बिजली लाइन डालना, 24 घंटे सात दिन पानी योजना के कार्य एक्सटेंशन दिए जाने के बाद किसी तरह हो पाए. आज भी कई जगह भूमिगत नाली, बिजली, पानी की पाइपलाइन बिछाने के कार्य व राइट टाउन स्टेडियम के दूसरे फेज के कार्य अधूरे हैं.

यूजीसी के नए नियमों का देशव्यापी विरोध

पिछले साल फरवरी में यूजीसी ने इन नियमों के मसौदा संस्करण को सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया था, जिसमें ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को जाति-आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था और भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट थी. मसौदा नियमों में यह भी प्रस्ताव था कि भेदभाव की झूठी शिकायतों को 'हतोत्साहित' किया जाए और इसके लिए जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया था. लेकिन अंतिम अधिसूचित नियमों में यूजीसी ने ओबीसी को जाति-आधारित भेदभाव के दायरे में शामिल किया है और झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधान को हटा दिया गया है. साथ ही, 'भेदभाव' की परिभाषा को थोड़ा विस्तृत किया गया है, ताकि इसमें साल 2012 के विनियमों में शामिल कुछ बिन्दुओं को लिया जा सके.

इसके अतिरिक्त जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए प्रत्येक परिसर में समानता समितियों (इक्वेलिटी कमेटी) के गठन को अनिवार्य कर दिया गया है. इनका पालन न करने पर संस्थान को डिग्री या कार्यक्रम प्रदान करने से रोकने जैसे दंड का सामना करना पड़ सकता है. जाति-आधारित भेदभाव का अर्थ यह है कि केवल जाति या जनजाति के विश्वविद्यान्नय अनुदान आयोग बनाने की मांग की थी.

जनवरी 2016 में तेलंगाना में रोहित वेमुला और मई 2019 में पायल ताडवी की आत्महत्या मामलों के बाद पीडति परिजनों ने 29 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके जातीय भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए कठोर नियम किया, जिसकी समीक्षा शिक्षा, महिला व युवा मामलों की संसदीय समिति ने की और 8 दिसंबर 2025 को अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपी. यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था और 15 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया गया. यह विनियम 2012 से लागू भेदभाव-रोधी नियमों का संशोधित रूप है.

आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के सदस्यों के खिलाफ किया गया भेदभाव है. भेदभाव की परिभाषा किसी भी हितधारक के खिलाफ, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता या इसमें से किसी भी आधार पर किया गया अनुचित, भिन्न या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई भी कार्य भेदभाव के अंतर्गत शामिल किया जाएगा.

✍ शाहिद ए चौधरी

निशानेबाज

क्या है मागा और वागा, टूटने लगा दोस्ती का धागा

पड़ोसी ने कहा, निशानेबाज, मागा का मतलब है- मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अब अमेरिका वागा की राह पर चल निकला है. भारतीय-अमेरिकी उद्योगपति विनोद खोसला ने यह बात कही. वागा का अर्थ है- व्हाइट अमेरिका ग्रेट अगेन. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और टेस्ला व स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क की नीतियां केवल गोरे अमेरिकनों को रोजगार व ऊंचे पद देकर अमेरिका को तथाकथित रूप से महान बनाने की हैं. ट्रंप भूल गए कि एशिया के लोगों ने उनके देश को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, चीन के श्रमिकों ने अमेरिका का रेल नेटवर्क बनाया था. भारतीयों ने आईटी, चिकित्सा सेवा, बायोटेक्नोलॉजी, शिक्षा, उद्योग, अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया.

कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी भारतीय एस्ट्रोनॉट के कृतित्व को कैसे भूला जा सकता है. भारतीय मूल के हरगोविंद खुराना ने जीन या गुणसूत्रों की खोज पर नोबल प्राइज पाया था. फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न

सिन्हा के बड़े भाई भरत सिन्हा नासा में वैज्ञानिक थे. अमेरिकी राजनीति में अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, श्री थानेदार, पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व गवर्नर निक्की हेली, प्रमिला जयपाल, तुलसी गबार्ड का बड़ा नाम है. विवेक रामास्वामी एक बड़े उद्यमी हैं. एलन मस्क के वर्णभेदी रवैये पर नाराजगी जताते हुए वेंचर कैपिटलिस्ट विनोद खोसला ने भारतीय मूल के तकनीशियनों और वैज्ञानिकों से कहा है कि वह एलन मस्क की टेस्ला व स्पेस एक्स कंपनी छोड़कर उनके साथ काम करने आ जाएं.

हमने कहा, अमेरिका की तरक्की में भारतीय ब्रेन की बड़ी भूमिका है. गूगल के प्रमुख सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्या नडेला तथा आईबीएम के अरविंद कृष्ण का ट्रंप को चुनाव जिताने और फंड जमा करने में बड़ा योगदान रहा, लेकिन अब ट्रंप और एलन मस्क एहसानफरामोशी पर उतर आए हैं. प्रतिभाशाली भारतीयों को कम योग्यता वाले गोरों से कम वेतन दिया जाता है. पड़ोसी ने कहा, निशानेबाज, ट्रंप की राय है कि असली अमेरिकी वह है जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो, वह गोरा और ईसाई होना चाहिए. ऐसे लोगों को ही वह बढ़ावा देंगे.

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : कांति चतुर्वेदी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD 12156 - डॉ. सागर खादीवाला

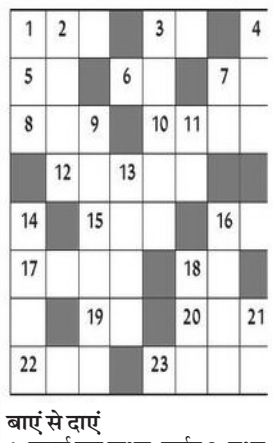

बाएं से दाएं

1. बड़ाई गुण कथन, वर्णन 3. मधुर, स्वादिष्ट 5. पहर, तीन घंटे का समय 6. मित्र, प्रेमी, हिमायती (उर्दू) 7. मरहम लगा हुआ कपड़े या रुई का टुकड़ा 8. चराई की भूमि 10. जादू जानने या करने वाला 12. साथ में यात्रा करने वाला (उर्दू) 15. एक तरह का विषैला कीड़ा, रंग के विचार से घोड़े का एक भेद 16. ब्रम्हा के चौदह पुत्र जो मनुष्यों के मूल पुरुष माने जाते हैं 17. शोरगुल, हल्ला 18. काले रंग की एक धातु जिससे हथियार तथा यंत्र आदि बनाए जाते हैं 19. लाल, रंगा हुआ 20. विवाह के समय वर सहित कुछ लोगों का कन्या पक्ष के यहां जाना 22. मुसलमानों के शासन काल में किसी देश का प्रबंध कर्ता, किसी न्यायालय संबंधी किसी कार्यालय का प्रबंधकर्ता 23. अपरिचित, नासमझ

ऊपर से नीचे

1. शीतल मंद वायु, हवा 2. व्यर्थ (उर्दू) 3. नवाब सिराजुद्दौला की फौज का सिपहसालार जो अपनी गद्दारी के लिए जाना जाता है 4. हवा, पवन 7. फाल्गुन मास का आनंदोत्सव, उस उत्सव में गाया जाने वाला गीत 9. कृतघ्न (उर्दू) 11. बहुत अंतर पर, फासले पर 13. सीधापन, सादगी, निष्कपटता 14. नाखूनों से नोचना 16. बहुत बड़ा राजा 18. एक प्रकार का सुगंधित गोंद जो जलने तथा दवा के काम आता है 21. शरीर, देह

Solution 12155

नि	त्या	नं	द		भा	व	ज
द्रा		दी	वा	ना			ग
	चि				अ	ध	म
पु	त्र	व	ती		नि		गा
रं	क		ज	टि	ल		ह
द	ला	ल				की	ट
र		क	छा	र		क	
	गा	ड़ी	वा	न		र	द्द

ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में सामाजिक कार्यों में ख्याति मिलेगी, नई योजनाओं में परामर्श होगा, वर्ष के मध्य में भूमि भवन आदि के मामलों में सफलता मिलेगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, वर्ष के अन्त में राजनैतिक क्षेत्र में विवाद होगा, व्यापार व्यवसाय में भागदौड़ करना होगी, निकट संबंधी के कारण मानसिक तनाव रहेगा.

मेष और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के व्यापार में भागदौड़ रहेगी, वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को राजनैतिक क्षेत्र में विवाद होगा, कर्क राशि के व्यक्तियों को निकट संबंधी के कारण मानसिक तनाव मिलेगा, मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों को व्यापार में भागदौड़ रहेगी, धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को आपसी तनाव रह सकता है, सिंह राशि के व्यक्तियों को भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी. मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को कम मेहनत में अच्छी सफलता के योग है.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक बुद्धिमान, चतुर, भाग्यवान, तथा परिश्रमी रहेगा, जिस कार्य को ठान लेगा, उसे पूरा करके ही छोड़ेगा, शिक्षा अच्छी होगी, व्यापार और नौकरी दोनों में अच्छी तरक्की करेगा, धार्मिक कार्यों में झुकाव रहेगा.

उदयकालीन ग्रह चाल

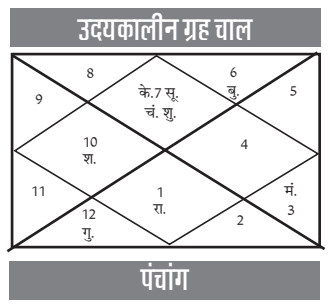

पंचांग

रा.मि. 10 संवत् 2082 माघ शुक्ल द्वादशी भृगुवासरे दिन 9/21, आर्द्रा नक्षत्रे रात 2/28, वैधृति योगे शाम 4/5, बालव करणे सू.उ. 6/35, सू.अ. 5/25, चन्द्रचार मिथुन, पर्व-प्रदोष व्रत, भीष्म द्वादशी, तिल द्वादशी, शु.रा. 3,5,6,9,10,1 अ.रा. 4,7,8, 11,12,2 शुभांक- 5,7,1.

व्यापार भविष्य

माघ शुक्ल द्वादशी को आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से गुड़ खांड चीनी, में पूर्व की चाल रहेगी, जीरा, धनियां, हल्दी में मंदी होगी, सोना, चांदी, में उतार चढ़ाव रहेगा, वायदा विचार आज जिस कार्य में वस्तु के भाव टूटें उसी में अगले दिन तेजी होगी. भाग्यांक 2607 है.

मेष-मतभेद दूर होने से रिश्ते मजबूत होंगे, रूखे व्यवहार से मित्र वर्ग नाराज होगा, पुराना कार्य बनेगा, अचानक धन लाभ होने का योग है.

वृषभ- डूबा धन मिलने के आसार है, अपनों के व्यवहार से खिन्नता होगी, व्यवसाय से लाभ होगा, मित्रों से मतभेद हो सकता है. सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी.

मिथुन- सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों से अच्छा लाभ होगा, सुख सुविधा के सामान पर खर्च संभव है, भूमि भवन मकान आदि के कार्यों में समस्या का समाधान होगा.

कर्क- कार्य के संबंध में अनुकूल आश्वासन मिलेंगे, लापरवाही से काम पूरे नहीं होगे, दिदनचर्या नियमित रहेगी, परिश्रम अधिक करना होगा.

सिंह- दुविधा की स्थिति में फैसला लेना मुश्किल होगा, गुमी वस्तु मिलने का योग है, पारिवारिक दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी, परिश्रम अधिक करना होगा.

कन्या- अपने लोग ही उलझाने का प्रयास कर सकते हैं, मांगलिक कार्य पर विचार होगा, मान सम्मान में वुद्धि होगी, व्यक्ति विशेष की सलाह लेना हितकर रहेगा.

तुला- सामूहिक कार्य में सभी की सलाह लाभदायक रहेगी, बुजुर्गो के स्वास्थ्य की चिन्ता रहेगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

वृश्चिक- बातों बातों में नई शुरूआत हो सकती है, जरूरतें पूरी करने उधारी संभव है, पुराने पेंडिंग पड़े कार्य बनेंगे, योजनाओं का विस्तार होगा.

धनु- राजकीय मामलों में लापरवाही से नुकसान होगा, शादी विवाह की चर्चा में सफलता मिलेगी, अधूरे कार्यों में गति आयेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी.

मकर- धार्मिक आयोजन में खर्च होगा, न चाहते हुये भी लोगों की आलोचना झेलना पड़ सकती है, सोचे कार्य बिलंब से होंगे, विवादों का समाधान होगा.

कुम्भ- कानूनी पक्ष मजबूत होगा, करीबी लोगों के व्यवहार से दुख होगा, मानसिक अस्थिरता रहेगी, नियमित कार्यों में व्यवधान आ सकता है.

मीन- सुविधा की कमी से कार्य में मुश्किल आयेगी, अनुभव का लाभ मिलेगा, नौकरी तथा राजकीय कार्यों में अच्छा समाचार मिलेगा, रोगी की चिन्ता रह सकती है.

SUDOKU 7288

5	9		1		2		3	8
			4		5			
2								5
		3		5		4	8	
	7						1	
	5	8		6		9		
8								1
			2		9			
3	4		6		7		5	2

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. ■ पहेली का केवल एक ही हल है.

नवभारत सू-दोकू 7287

4	6	2	3	5	8	9	1	7
8	1	7	9	2	6	3	5	4
3	5	9	1	7	4	8	2	6
6	4	1	5	3	7	2	8	9
2	7	5	8	4	9	6	3	1
9	3	8	2	6	1	4	7	5
1	2	3	6	9	5	7	4	8
5	9	4	7	8	2	1	6	3
7	8	6	4	1	3	5	9	2